Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

वैश्विक अर्थव्यवस्था और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका : एक संक्षिप्त अध्ययन

डॉ. कुसुम लता*

* सह आचार्य (राजनीति विज्ञान) महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – ब्रिक्स (BRICS) विश्व की पाँच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका का समूह है। यह संगठन वैश्विक आर्थिक संतुलन, विकासशील देशों के हितों की रक्षा तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस शोध-पत्र में ब्रिक्स की उत्पत्ति, उद्देश्य, आर्थिक प्रभाव, चुनौतियाँ तथा भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स वैश्विक आर्थिक शासन में पश्चिमी प्रभुत्व को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है तथा विकासशील देशों के लिए वैकल्पिक वित्तीय संरचना उपलब्ध करा रहा है।

शब्द कुंजी – ब्रिक्स, अर्थव्यवस्था, विकासशील देश, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था।

प्रस्तावना – 21वीं शताब्दी में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में तीव्र परिवर्तन हुए हैं। विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील देशों की आर्थिक शक्ति भी बढ़ी है। इसी संदर्भ में ब्रिक्स समूह का उदय हुआ। वर्ष 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओश्नील ने 'BRIC' शब्द का प्रयोग पहली बार किया। बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर यह 'BRICS' बन गया।

ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा वैश्विक संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

ब्रिक्स की उत्पत्ति एवं विकास – ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक सहयोगी अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और अपने सदस्यों के वैश्विक राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए की गई है। यह संक्षिप्त नाम मूल रूप से ब्राजील रूस, भारत और चीन के लिए था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था।

ब्रिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्थशास्त्री जिम ओ नील (Jam O' Neill) ने 2001 में किया था। इस समूह ने 2006 के G-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन में औपचारिक सहयोग शुरू किया, और वर्ष 2009 में रूस में अपना पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। ब्रिक्स देशों की पहली औपचारिक बैठक 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुई। इसके बाद यह संगठन लगातार विस्तारित होता गया। ब्रिक्स (BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa) में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा ब्रिक्स में इथियोपिया, ईरान, यूएई, और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल होने जा रहे हैं।[1]

मुख्य उद्देश्य – ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्यों में सदस्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा IMF जैसे वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार करना एवं डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों की स्थापना करना शामिल है। इसका उद्देश्य पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करना और अधिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत करना है।

BRICS अपने सदस्य देशों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना। तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को प्रोत्साहन देना।[2]

शिखर सम्मेलन – 17 वां शिखर सम्मेलन ब्राजील की अध्यक्षता में 2025 में किया गया । 18वां शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता की कमान भारत को सौंप गई। भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की कमान 1 जनवरी 2026 को आधारित आधिकारिक तौर पर ब्राजील से कमान संभाली है और सितंबर 2026 में भारत के नई दिल्ली में यह सम्मेलन की मेजबानी निर्धारित की गई।

मुख्य लक्ष्य और प्राथमिकताएं – भारत की अध्यक्षता का मुख्य विषय (Theme) 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' (building For Resilience,innovation,cooporation and sustainability) है।

- **ह्यूमैनिटी फर्स्ट –** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता पहले के दृष्टिकोण पर जोर दिया है जो विकासशील देशों की तकनीकी और डिजिटल जरूरत को प्राथमिकता देता है।
- **वैश्विक प्रशासन में सुधार–** भारत बहुपक्षीय संस्थानों जैसे (उन, IMF or World Bank) में सुधार की वकालत कर रहा है ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती मिले।
- **आतंकवाद का विरोध–** भारत ने समूह के भीतर आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुख था से उठाया है और इसके खिलाफ सामूहिक कार्यवाही पर जोर दिया है [3]

ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो समावेशिता, संवाद और साझा विकास का प्रतीक है।यह लोगो,परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम है, जिसमें

पंखुड़ियाँ सभी ब्रिक्स सदस्यों के जीवंत रंगों को दर्शाती हैं और सामूहिक शक्ति और एकता का प्रतीक हैं। केंद्र में, 'नमस्ते' का भाव स्नेह, सम्मान और सौहार्दपूर्ण सहयोग को दर्शाता है।

3. इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' है। यह ब्रिक्स के लिए प्रधानमंत्री के 'मानवता सर्वोपरि और जन-केंद्रित' दृष्टिकोण से प्रेरित है।[4]

4. वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका – वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका को हम निम्न अनुसार देख सकते हैं:

- **आर्थिक योगदान–** ब्रिक्स देश विश्व की बड़ी जनसंख्या और विशाल बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में विश्व की लगभग 40% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में निवास करती है।वैश्विक ळक्त में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।

ऊर्जा, कृषि, विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इनकी भूमिका तेजी से बढ़ रही है।

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) –** 2014 में ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। इसका उद्देश्य विकासशील देशों को आधारभूत संरचना और सतत विकास परियोजनाओं हेतु वित्ता उपलब्ध कराना है।

न्यू डेवलपमेंट बैंक को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विकल्प के रूप में देखा जाता है।

इसके अलावा ब्रिक्स के द्वारा कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट(CRA) ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज और विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार (Science, technology and innovation STI), फ्रेमवर्क प्रोग्राम (2015) शामिल है

भारत और ब्रिक्स – भारत के लिए ब्रिक्स कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है: वैश्विक मंच पर प्रभाव में वृद्धि,व्यापार और निवेश के अवसर,ऊर्जा सुरक्षा,आतंकवाद विरोधी सहयोग, तकनीकी और डिजिटल सहयोग आदि।

भारत ब्रिक्स के माध्यम से 'वैश्विक दक्षिण' (Global South) की आवाज को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। ब्रिक्स के 18 वा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा 2026 नई दिल्ली में प्रस्तावित है। [5]

ब्रिक्स के समक्ष प्रमुख चुनौतियां – ब्रिक्स के समक्ष कई प्रमुख चुनौतियां उपस्थित है जिनका ब्रिक्स सामना कर रहा है जिनमें से निम्न है :-

भू- राजनीतिक और रणनीतिक मतभेद – चीन, भारत और रूस ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को लेकर आंशिक रूप से भिन्न तथा परस्पर प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण रखते हैं जिसके कारण ब्रिक्स के एजेंडा, प्रतिनिधित्व और भविष्य की दिशा को लेकर सूक्ष्म स्तर पर प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है।

बाह्य दबाव और राजनीतिक दबाव– ब्रिक्स को विशेष रूप से डी-डालराइजेशन के प्रयासों को लेकर अमेरिका जैसे देशों से प्रत्यक्ष बाहरी दबाव का सामना करना पड़ता है। दंडात्मक परिणामों, शुल्क और सदस्यों के गठबंधनों की आलोचना संबंधी चेतावनियां दर्शाती हैं कि ब्रिक्स में भागीदारी भू- राजनीतिक दबाव को आकर्षित करती है, जिससे पश्चिमी संबंधों के साथ समझौते करने पड़ते हैं।

आर्थिक असमानता– चीन ब्रिक्स के कुल जीडीपी का लगभग 70% योगदान देता है, जिससे प्रभाव, निर्णय निर्माण और संसाधन योगदान में असंतुलन उत्पन्न होता है और चीन का प्रभुत्व प्रभावित करता है।

ब्रिक्स के विस्तार सामंजस्य से समस्या – ब्रिक्स में वर्ष 2024 के बाद विस्तार हुआ है जिसमें मिश्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया आदि देश ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। जिससे गुट के कमजोर पडने तथा और अन्य गुटों का बना तथा विविध प्राथमिकताओं के कारण निर्णय निर्माण की गति धीमी होने का जोखिम है तथा ब्रिक्स के पास सामूहिक सुरक्षा ढांचे का अभाव है जिससे कठोर सुरक्षा मुद्दों और संकट प्रबंधन पर इसकी विश्वसनीयता सीमित रहती है।

यद्यपि ब्रिक्स की उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण हैं, फिर भी कई चुनौतियाँ मौजूद है इसमें मुख्य रूप से सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद,आर्थिक असमानता,चीन का बढ़ता प्रभाव,पश्चिमी देशों का दबाव,साझा नीति निर्माण में कठिनाई,विशेष रूप से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद संगठन की एकता को प्रभावित कर सकते हैं।[6]

सुझाव एवं भविष्य की संभावनाएं –ब्रिक्स अपने आप को सशक्त करने के लिए कई सुझावों को अपना सकता है जिसके माध्यम से वह एक प्रभावशाली ग्रुप के रूप में प्रदर्शन कर सके।

संस्थागत और वित्तीय सुदृढीकरण – ब्रिक्स भविष्य में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में और अधिक प्रभावशाली बन सकता है। यदि सदस्य देश आपसी सहयोग बढ़ाते हैं, तो यह संगठन डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे सकता है।विकासशील देशों के लिए नया आर्थिक मंच बन सकता है। वैकल्पिक वित्तीय तंत्र विकसित कर सकता है।

हाल के वर्षों में कई देशों ने ब्रिक्स सदस्यता में रुचि दिखाई है, जिससे इसका वैश्विक महत्व और बढ़ा है। ब्रिक्स को एकीकृत डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म को कार्यान्वित करना चाहिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक(NDB) के माध्यम से स्थानीय मुद्राओं में ऋण देने का विस्तार करना चाहिए तथा हरित ऊर्जा और रणनीतिक क्षेत्र के लिए समर्पित कोष स्थापित करने चाहिए।

समन्वित कूटनीति और ग्लोबल साउथ के साथ समन्वय – वैश्विक शासन सुधारो पर ब्रिक्स के साझा और संस्थागत रूप को औपचारिक रूप प्रदान करना, क्षेत्रीय संघर्षों (जैसे सूडान हैती) के लिए संकट कूटनीति तंत्र विकसित करना तथा अफ्रीकी संघ एवं आसियान जैसे समूहो के साथ ब्रिक्स प्लस संवाद को संस्थागत बनाना, दक्षिण दक्षिण सहयोग, तथा ब्रिक्स के कूटनीतिक प्रभाव को और मजबूत करेगा।

नीति क्रियान्वयन के लिए स्थाई संस्थागत ढांचा – ब्रिक्स के पास में एक स्थाई संस्था का अभाव है जो कि इसकी नीतियों का सफल क्रियान्वयन कर सके। ब्रिक्स को चाहिए कि वह एक स्थाई संस्थागत ढांचा तैयार करें जिससे कि उसकी नीतियों का क्रियान्वयन सफल रूप से किया जा सके।[7]

निष्कर्ष – ब्रिक्स 21वीं सदी की उभरती हुई आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है। यह संगठन वैश्विक आर्थिक संतुलन स्थापित करने तथा विकासशील देशों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि आंतरिक चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं, फिर भी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में ब्रिक्स का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। बहूध्रुवीयता को बढ़ावा देने में ब्रिक्स एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में स्थापित हुआ है जो अपनी आर्थिक शक्ति और संस्थागत नवाचारों का लाभ उठा रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://theprayasindia.com/brazil-hands
2. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-

news-editorials/strategic-vision-in-the-evolving-brics-landscape
3. https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/40585/Launch_of_BRICS_India_2026_Logo_Theme_ and_Website_by_the_External_Affairs_Minister
4. https://en.wikipedia.org/wiki/18th_BRICS_summit
5. https://m.economictimes.com/markets/stocks/news
6. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-update
7. https://theprayasindia.com/brazil-hands-over-brics-presidency-to-india-for-2026

****